नहीं रखी है। अब तो दंगे मां-बेटी, बहन-भाई और पति पत्नी के बीच में आ गये हैं जैसे कि पंजाब में। पंजाब और हरियाणा भी इस की लपेट में आ रहे हैं, जिस से देश की अखंडता और स्वतन्त्रता को खतरा पैदा हो गया है। इस की चर्चा सदन में अगले सप्ताह में होना जरूरी है, जिस से इस समस्या का समाधान निकल सके। मैं यह चाहूंगा कि इस को बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी समझ कर अगले सप्ताह लिया जाए।

—

दूसरा मंडल कमीशन के बारे में है, जिस के लिए मुझे धरना भी देना पड़ा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो सदन में रखी गई है, उस पर तुरन्त चर्चा होना बहुत जरूरी है क्योंकि राष्ट्र की 60 से 80 फीसदी जनता की आखें इधर लगी हुई हैं और अगर इस कमीशन की रिपोर्ट पर अच्छी तरह से बहस कर के इस को लागू किया जाए, तो बहुत सी समस्याएं राष्ट्र की हल हो जाएंगी।

ये दो बातें हैं, जिन को मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यवाही में लिया जाए।

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I am extremely grateful to the hon. Members for the valuable suggestions they have made. I will go through the proceedings and if I feel necessary I will bring them to the notice of the Business Advisory Committee.

श्री मनी राम बागड़ी : यह तो तुम्हारा वायदा था, भीष्म नारायण सिंह जी।

———

14.47 hrs.

EYES (AUTHORITY FOR USE FOR THERAPEUTIC PURPOSES) BILL— *Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we shall take up further consideration of the following motion moved by Shri B. Shankaranand on the 8th July, 1982, namely:—

"That the Bill to provide for the use of eyes of deceased persons for the therapeutic purposes and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Dr. Saradish Roy. You should be brief. I want that this Bill should be passed before we take up the Private Members' Business. Therefore, I would request the hon. members to be brief because it is the most non-controversial Bill.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार): प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट होना है, वह कब होगा ?

MR. DEPUTY SPEAKER: That has already been circulated.

DR. SARADIASH ROY (Bolpur): The Eyes (Authority for Use for Therapeutic Purposes) Bill is not a controversial one. It extends only to the Union Territory of Delhi where there are less democratic rights of the people. Whatever democratic rights they had have been snatched away in the last two years. I would request the hon. Minister to restore the democratic rights at an early date. This Bill provides for replacement of the Bombay Corneal Grafting Act which is in force in the territory of Delhi since 1964 by this Act. In the statement of the Minister nothing has been said regarding the operation of this Act—Bombay Corneal Grafting Act—for the last 18 years, that is, in operation in Delhi.

Regarding the number of donors or the eyes received and grafted, how many people of the lower income group have been benefited by this corneal grafting has

[Dr. Saradiash Roy]

not been stated in the Minister's statement. I want that this should be mentioned in the House by the hon. Minister. I also want to know how these eyes have been utilized?

This Act is a commendable one. In this Act corneal grafting has been provided, but no provision has been made for the preservation of the donated eyes and for the proper utilisation of the donated eyes. No indication has been given about the measures to prevent mis-utilisation of the donated eyes. This is a laudable Bill. But there should be scientific arrangements so that the donated eyes may be preserved for proper use. No guidelines have been mentioned as to how the receivers of these eyes will be selected.

In our country there are lakhs of people, especially people of the lower strata who lose their eye sight. If transplanting of cornea can be utilised, these people will be benefited. In the western parts of the country many people have lost their eyes and this Bill will benefit them.

This Act applies only to the Union Territory of Delhi. However, in some other States also similar Acts are there and it should be examined how these Acts are being implemented, and how far the provisions of the Acts are being utilised for the benefit of the poorer sections, because they are the people most affected. They have lost their eye sight due to mal-nutrition and shortage of drugs and mal-treatment. They should be benefited by this Act. I, therefore, request the hon. Minister to enlighten how this Bombay Corneal Grafting Act has benefited the people of Delhi during the last 18 years or so. With these words I support this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mool Chand Daga.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात अच्छी की है कि अन्धे आदिमियों को रोशनी देने के लिए मृत व्यक्तियों की आंखे काम देंगी । हिन्दुस्तान में 94 लाख अन्धे आदमी हैं । वे आज भी मौजूद हैं । उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कुपोषण के कारण अन्धे हो जाते हैं । आपने इस बिल को ला कर ठीक काम किया है और इसको पास करा कर आप नेत्रहीनों के लिए काम करेंगे ।

लेकिन मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि इसे आपने यूनियन टेरीटरी पर ही क्यों लागू किया है ? अगर यह चीज सारे भारत में लागू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा । इसमें आपने कहा है कि आईज बैंक्स कहां कहां पर बन सकते हैं, कहां कहां पर आईज डोनेट हो सकती है । दूसरे आपने कहा कि जेल के अन्दर या अस्पताल के अन्दर अगर वहां पर अफ़सर नहीं हो तो वह किसी को अथोराइज कर सकता है और जिसको वह अथोराइज करेगा, उसके द्वारा आंख का उपयोग किया जा सकता है ।

मैं यह सोचता हूं आपने यह बिल 1980 में पेश किया और आज 1982 में इसे पारित कराने के लिए आ रहे हैं । मुझे यह नहीं मालूम कि आज तक कितने लोगों ने अपने नेत्रदान किये और कितने लोगों के लिए उनका प्रयोग किया गया ?

आंखें लेने के बाद, उनको आइज-बैंक में रखने के बाद किस तरह से उनका उपयोग करेंगे, इसको कहीं डिफ़ाईन नहीं किया गया है, कहीं भी इसकी डेफ़ीनेशन नहीं दी गई है ।

इस तरह से यह जो बिल आपने पेश किया है, इसकी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह बिल सारे देश में लागू होना चाहिए और इस बिल में जो कमियां बताई गई हैं, जैसा कि बताया गया है कि बांबे के अन्दर यह कमियां थीं, इसलिए अमेंडमेंट लाया गया है, अभी भी मैं समझ रहा हूं कि यह बिल पूर्ण रुप से ठीक नहीं है । इसलिए

जो सुझाव और अमेंडमेंटस मैंने दिए हैं, उन पर गौर करें। जो मैंने संशोधन दिए हैं, जिन पर मैं संशोधनों के समय बोलूंगा उनकी तरफ़ ध्यान देंगे तो उससे आपको लाभ होगा और बिल अच्छा बन सकता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आज हमारे सामने विचाराधीन है, इस बिल का मानवीय दृष्टिकोण तो बड़ा उत्तम है और हम लोग इसकी सराहना करते हैं। लेकिन इस बिल को पेश करने में कुछ जल्दी कर दी गई है– ऐसा लगता है या इस पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया है। मानवीय पक्ष अच्छा होते हुए भी भारतीय समाज में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका कोई अंग निकाल लेना या भंग कर देना बहुत ही बुरा माना जाता है। यदि किसी को चेचक भी निकलती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाया नहीं जाता, संस्कार में जलाना आवश्यक है। इसलिए मान्यवर मैं समझता हूं कि बिल स्वीकृत करने के पूर्व और बाद में एक सामाजिक वातावरण बनाना बहुत आवश्वयक है। इस तरह का इस बिल में उपबन्ध होना चाहिए।

सामाजिक जागृति लाने के बाद हमको यह देखना होगा कि ये जो आंख निकालने वाले डाक्टर होंगे, ये किस परिस्थिति में आंखें निकालेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसा कि बिहार की जेलों में हुआ, कहीं उत्पीड़न आदि में आंखें निकाल ली जाती हैं—ऐसा तो नहीं होगा। इन डाक्टरों की योग्यता क्या होगी? इनको कहां तक प्रशिक्षित किया जाएगा और जिस व्यक्ति की आंखें निकाली जाऐंगी, उसके स्वास्थ्य की जांच कैसे होगी — क्या क्राइटेरिया होगा, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार से जैसा कि डागा साहब ने कहा है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इसको केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था हो तो यह बड़ी अच्छी बात होगी किन्तु इसके लिए पहले हमें बहुत तैयारी करनी होगी।

इसी प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जो दुर्घटनाओं में मृतक आते हैं, क्या वहां के डाक्टरों को भी आंखें निकालने की इजाजत दी जाएगी। जिलों में जो शव गृह हैं, वहां भी देखना होगा कि डाक्टरों की योग्यता क्या होनी चाहिए।

आइज-बैंकों में जो आंखें रखी जाएंगी, इसके लिए कोई वित्तीय व्यवस्था है या नहीं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ब्लड-बैंकों में ब्लड दिया जाता है और उसका समुचित उपयोग नहीं किया जाता है, इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

15.00 hrs.

इसको मान भी लिया जाए कि जो आंखें निकाली जाएंगी उनको ठीक ढंग से रखा जाएगा और उपयुक्त डाक्टर भी निकालने के लिए होंगे तो भी सवाल पैदा होता है कि किस प्रकार के व्यक्तियों पर इनको लगाया जाएगा? उन पर लगाया जाएगा जिन के पास करोड़ दो करोड़ या दस करोड़ होंगे, जो पैसा खर्च करने के लिए सक्षम होंगे या उन गरीबों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा जिन के आखें नहीं हैं और अंधेपन के कारण उनको भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है? अच्छे व्यक्तियों के लिए, गरीब लोगों के लिए देश और जन हित में इनका उपयोग होना चाहिये। यह बिल बहुत अच्छा है। इस वास्ते इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): Sir, I welcome this Bill, as also the amendment proposed by the hon. Minister with regard to the use of these eyes. While Participating in a Private Members' Bill, moved by Prof. Madhu Dandavate, on 20th March 1980, I pointed out some of the figures relating to total blindness in our country. It is said that over 9 to 10 million people are blind in India, out of which 5 million are blind due to cataract, 12,000 children below the age of 12 go blind every year and that more than 30 per cent of the children below the age of 21 go blind due to lack of nutritious food. You may very well ask why I am referring to all these figures. I am doing so because the opening sentence of the Statement of Objects and Reasons says:

> "Modern science has rendered possible the use of eyes of deceased persons for restoring sight to blind persons."

Modern science has also revealed the possibility to prevent blindness, especially among children. Therefore, I want to know what Government propose to do in this respect.

Clause 1 of the Bill says that it extends to the Union Territory of Delhi. It is a fact this is a State subject for entry 6 of the State List reads "public health, sanitation, hospitals and dispensaries". Therefore, the Central Government may not be able to do much in this respect. But my submission is that this must be a model enactment, to be followed by the States in the larger interests of the blind people of this country. About 4,500 children of school-going age are blind in Delhi alone. Over 6 lakhs of people are blind in Delhi. This is the magnitude of the problem. Therefore, while the attempt of the Central Government is a welcome move, it should be extended to other Union Territories also. I do not understand what is restrainning the Central Government from extending it to other Union Territories as well.

Then, what is the meaning of "therapeutic purposes"? According to the dictionary, it is curative. But, is it to be confined to the curative aspect alone? As Shri Daga said, it should have been defined in the definition clause itself. We would like to know how far the therapeutic purposes, as mentioned in the opening speech of the Minister, will be implemented.

Then I come to clause 6, which gives the Government authority to remove eyes from bodies of persons involved in accidents. I went through the number of accidents which took place in our country in 1980 and I found that the number of road accidents was 1,35,900 out of which 20,230 were killed. So, you can imagine the usefulnes of the enactment.

Clause 7 deals with the preservation of the eyes removed from dead bodies. Have you mentioned anywhere how the eyes collected shall be distributed? I find that even in the rule-making clause it is not mentioned. Therefore, may I request the hon. Minister to bring forward an amendment to clause 7, to provide for the equitable distribution of these eyes?

In the financial Memorandum it is said:

> "This will be met from outside the normal budgetary grants for eradication of blindness."

This is a tricklish sentence. I would like to know how much money we have spent in this respect, what is the allotted money, how much we have spent and how many people are cured of this blindness.

Sir, on the whole, this is a model enactment which other States also ought to be advised by the Government to imitate. Therefore, blindnes in our country can be curtailed to that extent.

With these words, I welcome this Bill as well as...

AN HON. MEMBER: With amendment.

SHRI XAVIER ARAKAL: With amendment of course. The Minister has said that it is going to be amended.

With these words, I welcome this Bill.

*SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam, I

*The original speech was delivered in Tamil.

wish to say a few words supporting the Eyes (Authority for use for therapeutic purposes) Bill, 1980, which has been introduced by our hon. Minister of Health, Shri Sankaranand.

Since the Bombay Corneal Grafting Act, 1957, as extended to the Union Territory of Delhi, has been found to be deficinet in certain respects, this bill has been brought forward exclusively for the Union Territory of Delhi. I am happy that at least after 18 years of working of this defective and deficient Bombay Act this legislative attempt has been made by the Government. If this Bombay Act has been found to be deficient in Delhi, it should be equally so in Maharashtra. I wonder how many mishaps have taken place in Maharashtra during the past 25 years when this Act is in force there. After all the people in Delhi and in Maharashtra are the citizens of our country. I request the hon. Minister of Health to instruct the Maharashtra Government to make necessary amendments to this Act, on the lines of Delhi Bill. I would even go to the extent of saying that this Delhi Bill should replace the Act in Maharashtra, which is defective and deficient.

It has become a common feature that even M.B.B.S. doctors undertake eye operations. Cataract operations are being conducted by inexperienced and novice Doctors. It need not be said that eyes are the most sensitive organs of the human body and the greatest care has to be taken about the treatment of the eyes. Many eminent medical men, both nationally and internationally, have averred that India has the largest number of blind people in the world. Many State Governments have taken up programmes for giving vision to the blind. When D.M.K. was in power in Tamil Nadu, our Government held many eye-camps under the charge of world-renowed eye-surgeons like Dr. Venkatasamy. Today, unfortunately, the eye-camps are being held under hte charge of inexperienced Doctors. I request the hon. Minister of Health to issue strict directives that eye-camps should be conducted by experienced eye-doctors.

I would like to another important issue. In this Bill it has been stated that the person who wants to donate his eyes after his death should give authorisation in the presence of two or more witnesses—Clause 3 of the Bill—and at least one among them should be a near relaitve like spouse, parent, son, daughter, brother or sister. It may happen that a person meets with an accident and at that time none of his relatives is near him.Does it mean that he cannot donate his eyes without this kind of authorisation? I demand that Claues 3 of this Bill should be suitably amended as to incorporate that the person wanting to donate his eyes after his death need give oral or written declaration to that effect.

15.11 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

This Bill is a wholesome legislative measure which will enable the Government to have eye-banks for the benefit of blinds in the country. This should not be confined to the Union of Territory alone; it should be extended to the whole country. I commend this Bill to the unanimous approval of this House.

श्री गिरधारी लाल व्यास : (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह जो नेत्र चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक यहां उपस्थित किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर दुनियां के मुल्कों के मुकाबले सब से ज्यादा अन्धे लोग हैं । लोग अन्धे किस प्रकार होते हैं, इसके बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी दी है कि कुपोषण की वजह से. . . .

अध्यक्ष महोदय : आप जरा रुकिये, प्रधान मंत्री स्टेटमैंट करेंगी ।

15.13 hrs.

STATEMENT *RE.*: SITUATION IN LEBANON

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Will you allow clarification afterwards?